भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 555

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन के विकास हेतु सार्वजनिक-निजी उद्यमों की स्थापना

555. श्री राहुल कस्वां:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त उद्यमों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क), (ख) और (ग): पर्यटन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्रोत्साहन सहित पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है । देश में पर्यटन के विकास हेतु सार्वजनिक निजी उद्यम की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है । तथापि पर्यटन मंत्रालय ने सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र में निवेश तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी को सुसाध्य बनाने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, औद्योगिक हितधारकों आदि के सदस्य शामिल हैं ।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु 5303.64 करोड़ रु. की राशि से देश में 76 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसमें राजस्थान में 283.47 करोड़ रु. की राशि से स्वीकृत 4 परियोजनाएं शामिल हैं । पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में स्वदेश दर्शन

योजना को रूपांतरित किया है और राजस्थान में विकास हेतु 'बूंदी (केशोरायपाटन)' तथा 'जोधपुर' सहित देश में 55 गंतव्यों को चिह्नित किया है । पर्यटन मंत्रालय ने अपनी 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' योजना के अंतर्गत राजस्थान में 32.64 करोड़ रु. की राशि से वर्ष 2015-16 में स्वीकृत 'पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास' की एक परियोजना सहित देश में 1630.00 करोड़ रु. की राशि से 46 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है । इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी योजना के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है और वर्ष 2022-23 में 17.68 करोड़ रु. की राशि से 'सीमा सुरक्षा बल चेक पोस्ट, तनोट परिसर में सीमा पर्यटन के विकास' की परियोजना को स्वीकृति दी गई है । पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सोशल मीडिया संवर्धन, विभिन्न विपणन कार्यकलापों, आयोजनों में भागीदारी, वेबसाइटों, वेबिनारों आदि के माध्यम से भी देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है ।

*****